(ख) क्या भारी मात्रा में फलों का उत्पादन होने के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में फलों के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.50 प्रतिशत ही है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि देश में उत्पन्न किये जाने वाले फलों का बहुत बड़ा भाग बिना उपयोग किए ही नष्ट हो जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार देश को प्रतिवर्ष कुल कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(च) क्या सरकार ने इस हानि को कम करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं; यदि हां, तो ये लक्ष्य क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) से (च) एफ ए ओ ईयर बुक 1992 के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है जिसका कुल फल उत्पादन 30 मिलियन टन है। विश्व का अनुमानित फल उत्पादन 370 मिलियन टन है।

कोई सरकारी आकलन उपलब्ध नहीं है किन्तु विश्व के व्यापार में भारत का हिस्सा 0.5 प्रतिशत से कम होने का अनुमान है।

यद्यपि उपयोग के बिना फलों के खराब होने का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है किन्तु यह अनुमान है कि अपर्याप्त फसलोत्तर बुनियादी ढांचे और उत्पाद में खराबी आने के कारण फलों और सब्जियों की गुणवत्ता में खराबी और कीमतों का नुकसान करीब 25 से 30 प्रतिशत तक होता है। परन्तु फलों की पर्याप्त मात्रा का उपयोग परिरक्षण आदि के लिए घरेलू और असंगठित क्षेत्र में किया जाता है अतः उपयोग में न लायी गयी निबल मात्रा 5% से अधिक नहीं होगी।

नुकसान को कम करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये हैं लेकिन यह अनुमान है कि फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापित क्षमता आठवीं योजना के आरंभ में 9.5 लाख टन से बढ़कर योजना के अंतिम वर्ष में 20 लाख टन हो जायेगी। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन और सहायता देने के अलावा सरकार फलों और सब्जियों के लिए विभिन्न फसलोत्तर प्रसंस्करण और संचालन सुविधाएं स्थापित करने के वास्ते भी सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इन उपायों से नुकसान में काफी कमी आने की आशा है।

Negotiations on Transit Facilities between India and Bangladesh

*32. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is an ongoing negotiation between India and Bangladesh on transit facilities;

(b) if so, what is the extent of the proposed transit facilities;

(c) whether there has been any proposal to include army movement in the proposed transit facilities; and

(d) what has been the progress in the negotiations?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): (a) Government of India have been interested in securing transit facilities through the Bangladesh territory and have taken up the matter on a number of occasions, at various levels, with the Government of Bangladesh.

(b) Government of India have proposed various modes of transit arrangements to the Government of Bangladesh such as road, railways and using Chittagong harbour as a part of multimodal transit facilities.

(c) No, Sir.

(d) The Government of Bangladesh, so far, have not reacted positively to our proposals.

Shifting of Villages of Uri-Kupwara sector on Border of Kashmir

*33. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS to pleased to state:

(a) whether Government have received a proposal from the border security force to shift some 40 villages on the border of Kashmir in the Uri-Kupwara sector and